उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
E-mail :infodirector.uk@gmail.com
Website :www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 09 सितम्बर, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–07(09/47)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए राजस्व अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण एवं फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिये सब रजिस्ट्रार व राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने को कहा। उन्होंने म्यूटेशन के मामलों में कम से कम समय के निर्धारण तथा इससे होने वाली जन असुविधाओं के निराकरण पर ध्यान देने को कहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने भू अभिलेखों के रखरखाव व अद्यतनीकरण पर विशेष ध्यान देने पर बल देते हुए पौड़ी व अल्मोड़ा जनपद में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत भूमि का एरियल सर्वे कराये जाने के निर्देश दिये, इससे वास्तविक कृषि भूमि व वन भूमि की भी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में समेकित राजस्व संहिता तैयार किये जाने के भी निर्देश सचिव राजस्व को दिये हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के लिए पद आवश्यक हो, उन्हें भरने की अविलम्ब व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिये विशेष अभियान संचालित किया जाए।

देहरादून 09 सितम्बर, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–06(09/46)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भारत रत्न पं.गोविन्द बल्लभ पंत की जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में उन्हें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक बताया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पं.पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगारी प्रथा तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त इन बुराईयों को मिटाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पं.गोविन्द बल्लभ पंत के सिद्धांत हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 सितम्बर, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(09/45)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि चारधाम के बेहतर प्रबन्धन के लिये सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चारों धामों के बेहतर प्रबन्धन के लिये ही चारधाम विकास परिषद का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन धामों में हक हकूक धारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

चारधाम विकास परिषद के सदस्यों से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम के प्रति देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधायें देना हमारा दायित्व है। अतः इससे जुड़े सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी तथा यात्रा के बेहतर प्रबंधन के लिये कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि चारधाम विकास परिषद के अध्यक्ष को भी सदस्यों द्वारा पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए ताकि वे व्यवस्थाएं और बेहतर बना सकें।

इस अवसर पर चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष आचार्य शिव प्रसाद मंमगाई ने कहा कि चारों धामों की व्यवस्था चारों धामों पर बनायी जायेगी। हक हकूकधारी यथावत बने रहेंगे। चारधाम विकास परिषद के अध्यक्ष के स्तर पर चारों धामों में व्यवस्थाएं संचालित होती रहेंगी। उन्होंने चारों धामों के बेहतर प्रबंधन के लिये सभी से अपना सहयोग देने को कहा है।

इस अवसर पर श्री कृष्ण कान्त कोठियाल अध्यक्ष चार धाम हक हकूकधारी, श्री लक्ष्मी नारायण जुगरान कोषाध्यक्ष चार धाम हक हकूकधारी, श्री विनोद शुक्ला अध्यक्ष केदार सभा, श्री दीपक सेमवाल सचिव श्री गंगोत्री मन्दिर समिति, श्री पवन उनियाल पूर्व उपाध्यक्ष मन्दिर समिति यमनोत्री आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 सितम्बर, 2019(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(09/44)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की चुनौतियों का दक्षता के साथ सामना करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यातायात प्रबन्धन व ड्रग्स की प्रवृत्ति को रोकने, वाहन चोरी पर प्रभावी नियन्त्रण, संवेदनशील मामलों के अनावरण में तेजी लाने के साथ ही युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से रोकने के लिये स्कूल व कॉलेजों में नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान संचालित करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रदेश में आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये पृथक से थाने के गठन, हल्द्वानी में साइबर थाना, तथा डि–एडिक्शन सेन्टर की स्थापना के साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिये हैं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून में बहुउद्देशीय पुलिस भवन के निर्माण, थाना विविध निधि बढ़ाये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण हेतु 20 पी.सी.आर वाहनों के क्रय, पुलिस विभाग में कार्यरत अंशकालिक सफाई कार्मिकों का मानदेय 1500 से बढ़कर 3000 किये जाने तथा विचाराधीन बंदियों के भोजन व्यय को 45 रू. से बढ़ाकर 100 रू. करने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने ग्राम चौकीदारों को आपदा मित्र के रूप में भी प्रशिक्षित करने की भी बात कही, ताकि आपदा के समय उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर किये जाने वाले चालान के समय संबंधित कार्मिकों से आम जनता के साथ शालीनता से पेश आने को कहा है। ई–चालान व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें आपसी अनावश्यक बहस से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने केदियों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों से होने वाली आय का एक हिस्सा कैदियों को दिये जाने तथा होमगार्डों के बेहतर प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 के महाकुम्भ की सुरक्षा के दुष्टिगत प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिये है। उन्होंने के.पी.आई. के अन्तर्गत निर्धारित मानकों में अपेक्षित प्रगति के साथ ही प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदीय पुलिस अधीक्षकों से भी कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितिश झा, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी, डी.जी. लॉ एंड ऑर्डर श्री अशोक कुमार के साथ ही शासन एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 सितम्बर, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(09/43)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को नगर निगम देहरादून में हिन्दुस्तान समाचार पत्र द्वारा आयोजित ''हिमालय–बचाओ पॉलिथीन हटाओ ''कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमालय संरक्षण पर आधारित भाषण प्रतियोगिता में राज्य एवं जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हिमालय के संरक्षण की पहली जिम्मेदारी उत्तराखण्ड की है उत्तराखण्ड से निकलने वाली गंगा और यमुना से देश की 65 प्रतिशत सिंचाई होती है। इसीलिए हिमालय को वाटर टॉवर भी कहा जाता है। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए बृहद स्तर पर वृक्षारोपण करना जरूरी है। वृक्षों के संरक्षण के लिए विश्वेश्वर दत्त सकलानी, कल्याण सिंह रावत, गौरा देवी, सुन्दरलाल बहुगुणा ने अनेक प्रयास किये। वृक्षों व प्रकृति के प्रति हमारा स्वाभाविक लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो जिक्र किया है। जन सहयोग व जागरूकता से ही इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं किसी भी अभियान को तभी सफलता मिलती है, जब हम उसकी शुरूआत स्वयं से करते हैं।

मेयर श्री सुनील उनियाल गामा ने कहा कि हिन्दुस्तान समाचार पत्र हिमालय के संरक्षण व पॉलिथीन मुक्ति के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार व जन चेतना के माध्यम से सराहनीय कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चों की सहभागिता से बच्चों में प्र्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना का और अधिक संचार होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के माध्यम से देहरादून में प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लिया गया है।

इस अवसर पर बदरी–केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद थपलियाल, हिन्दुस्तान के स्थानीय संपादक श्री गिरीश गुरूरानी व गणमान्य उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 सितम्बर, 2019(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(09/42)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास, औद्योगिक विकास एवं आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक की। यह समीक्षा सीएम डेशबोर्ड के तहत की–परफोर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम डेशबोर्ड 'उत्कर्ष' को अपने डेस्कटॉप पर रखें। कार्यों के लिए जो प्रतिमाह का टारगेट दिया गया है, वो हर हाल में पूर्ण करें। कार्यों की लगातार मोनिटरिंग से कार्य प्रगति में तेजी आयेगी।

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आईएलएसपी आदि की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन पर अधिक बल दिया जाय। पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों में वृद्धि कर उनमें कार्य करने के आधुनिक तौर तरीकों को विकसित किया जाए। मनरेगा के तहत श्रमिकों का भुगतान समय पर हो। मुख्यमंत्री ने ग्रोथ सेंटरों की प्रगति की जानकारी भी ली। अभी तक 67 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। कुछ ग्रोथ सेटरों में जल्द कार्य शुरू किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी प्रयासों की जरूरत है। इसके लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगले साल से हरेला पर्व पर प्रदेशभर में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

बैठक में जानकारी दी गई कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 10420 लोगों को रोजगार दिया गया। जिसमें से 7543 लोगों को स्वरोजगार, 2573 लोगों को कौशल परक रोजगार दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस वर्ष अगस्त तक 645 आवास बनाने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 605 आवास बन चुके हैं। मनरेगा के अन्तर्गत 3705 लाख लीटर जल संरक्षण के सापेक्ष 3064 लाख लीटर जल संरक्षण किया गया। मनरेगा के तहत 99.54 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान हो चुका है।

औद्योगिक विकास विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कहा कि इन्वेस्टर समिट के बाद जो निवेश अभी तक प्रदेश में हुआ है, इसमें स्थानीय स्तर पर कितने लोगों को रोजगार मिला व किस क्षेत्र में रोजगार अधिक मिला इसका पूरा डाटा रखा जाए। उद्यमिता व एवं रोजगार की समग्र समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 'स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति' का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में औद्योगिक विकास विभाग में कुल 36047 लोगों को रोजगार दिया गया है।

आबकारी विभाग के समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि चैक पोस्ट और बॉर्डर क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए सघन चैकिंग की जाए। जिन स्थानों पर मदिरा की दुकाने नहीं बिकी हैं, ऐसे स्थानों पर भी निरीक्षण किया जाय कि इन स्थानों पर कोई अवैध रूप से शराब की बिक्री न कर रहा हो। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले वर्ष आबकारी से 2705 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई।

बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री सुशील कुमार, प्रभारी सचिव श्री एस.ए. मुरूगेशन, अपर सचिव श्री रामविलास यादव, श्री एच.सी सेमवाल व संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

पर्यावरण संरक्षण उत्तराखण्डवासियों के स्वभाव में : मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र

- **जल संरक्षण व संवर्धन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।**
- **पॉलिथीन के प्रयोग को सख्ती से रोका जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को भी रोका जाएगा।**
- **मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, हिमालय दिवस के अवसर पर हिमालयन यूनिटी मिशन, यूसर्क और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित किया।**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, उत्तराखण्डवासियों के स्वभाव में है। हरेला जैसे त्यौहार, हमारे पूर्वजों की दूरगामी सोच को बताते हैं। राज्य सरकार, हिमालय के संरक्षण के लिए संकल्पित है। पॉलिथीन के प्रयोग को सख्ती से रोका जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को भी रोका जाएगा। मुख्यमंत्री, हिमालय दिवस के अवसर पर सर्वे रोड़ स्थित डूंगा हाउस में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

हिमालयन यूनिटी मिशन, उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र और विज्ञान भारती, उत्तराखण्ड द्वारा संयुक्त रूप से ''हिमालय– विज्ञान, चिंतन व विवेचना'' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालय का राज्य व देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्व है। हिमालय के संरक्षण का दायित्व, हम सभी का है। हिमालय के संरक्षण के लिए यहां की संस्कृति, नदियों व वनों का संरक्षण जरूरी है। जल संरक्षण व संवर्धन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसहभागिता से जलसंरक्षण के लिए रिस्पना टू ऋषिपर्णा व कोसी नदी का पुनर्जीवन अभियान चलाए गए। प्रत्येक जिले में एक–एक वाटरशेड विकसित करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि इनमें अन्य लोगों के साथ बच्चे भी बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी से पेड़ नहीं बल्कि पेड़ से पानी होता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो पानी भी नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए किसी एक दिन को वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाएगा जिसमें कि पूरे राज्य में एक दिन में ही करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे। ऐसा करना सम्भव है। पूर्व में रिस्पना से ऋषिपर्णा अभियान में एक दिन में देहरादून में 2 लाख 50 हजार से ज्यादा पौधे लगाए गए थे जबकि कोसी पुनर्जीविकरण अभियान में एक दिन में 1 लाख 67 हजार से अधिक पौधे लगाए गए थे। सचिवालय में पानी की प्लास्टिक की बोतलों पर रोक लगा दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत में आयोजित हिमालयन कान्क्लेव में मसूरी संकल्प पारित किया गय था। इसमें सभी हिमालयी राज्यों ने हिमालय के पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया था। आरगेनिक व प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम सभी संकल्प लें तो जल संरक्षण का महत्वपूर्ण काम किया जा सकता है। टॉयलेट के सिस्टर्न में एक बोतल रख दें तो इससे एक बार में एक लीटर पानी बचाया जा सकता है। अगर राज्य में एक करोड़ टॉयलेट हों तो एक दिन में एक करोड़ लीटर जबकि एक वर्ष में 365 करोड़ लीटर पानी बचाया जा सकता है। सामाजिक चेतना व इच्छाशक्ति से ये सम्भव है।

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा.धनसिंह रावत, परमार्थ निकेतन के श्री चिदानंद मुनि जी, पद्मश्री अनिल जोशी, यूसर्क के प्रोफेसर दुर्गेश पंत आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग